www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

2 अमेरिका के टैरिफ अटैक से प्रभावित होंगे...

3 मान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं को नया...

4 भारत बनेगा प्रमुख आर्थिक शक्ति, व्यापार और...

वर्ष: 9 | अंक: 278 | दिल्ली, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को दिया जाएगा तकनीकी और बजट प्रशिक्षण-धामी

उत्तराखंड (एजेन्सी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अधिकारियों को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को एकीकृत प्रयास करने होंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गांवों के विकास से ही राज्य और देश का विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 'एकीकृत पंचायत भवनों' के निर्माण के निर्देश दिए। इन एकीकृत पंचायत भवनों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि के एक ही स्थान पर बैठने की व्यवस्था होगी। उनके एक साथ बैठने के लिए एक रोस्टर भी बनाया जाना चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे लोगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

भोपाल-इंदौर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

भोपाल-इंदौर (एजेन्सी)। सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, भोपाल के ज़िला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक सख्त निर्देश जारी किया है-बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को अब मध्य प्रदेश की राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश भोपाल ज़िले के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर लागू होगा। यह निर्णय बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पंप संचालक पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ईंधन पंप संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि वे आईएसआई-चिह्नित हेलमेट न पहनने वाले सवारों को ईंधन उपलब्ध कराते हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तेज प्रताप ने महुआ में शुरू किया प्रचार

बिहार (एजेन्सी)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव एक्शन में हैं। उन्होंने महुआ विधानसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया है। तेज प्रताप ने 'टीम तेज प्रताप' वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तेजप्रताप यादव ने कहा कि आज से महुआ के लिए मेरा चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि किसी ढोंगी पर विश्वास मत करो जो बच्चों की तरह रोने लगे। मेरी रगों में लालू यादव का खून है। अगर मुझे वोट दोगे तो लालू यादव को जिता दोगे... मुझे वोट दोगे तो बिजली मुफ़्त मिलेगी। इसके साथ ही तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो कृष्ण हैं और मैं अर्जुन, तो उन्हें बांसुरी बजाकर ये साबित करना चाहिए। तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि आज महुआ विधानसभा क्षेत्र के हरपुरा ओसती में जन संवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या आये हुए जनता-जनार्दन को संबोधित किया। महुआ को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने के बाद अब महुआ को महुआ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलवाने का काम करूंगा।

ट्रंप के 25 प्रतिशत टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल- भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के एक दिन बाद कही गई। उन्होंने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के फैसले का हवाला दिया। लोकसभा में बोलते हुए, गोयल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ट्रंप के 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के प्रभावों की जांच कर रही है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र ने ट्रम्प के बयान पर ध्यान दिया है और वर्तमान में इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। सरकार ने कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुँचने के लिए" बातचीत कर रहे हैं।

बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चीन और रूस के साथ व्यापार करने पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उनके ऊंचे टैरिफ और रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा खरीद ने उनकी नीतियों को लेकर चिंता है। खासकर तब जब दुनिया यूक्रेन में रूस की हिंसा रोकना चाहती है। इस आधार पर उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और एक एक्स्ट्रा पैनल्टी लगाने का ऐलान किया है।

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार भारत और रूस को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। इसके साथ ही भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ तेल डील को लेकर भी ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की महत्वपूर्ण बिक्री और खरीद के लिए छह भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।

विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव: रेखा गुप्ता

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी, भुगतान की प्रक्रिया होगी सुगम: सीएम

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, उसमें अधिक पारदर्शिता लाने और आर्थिक व्यवधान को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर ने कई आवश्यक बदलाव व महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन निर्णयों से तेजी से विकास कार्य होंगे और राजधानी आसानी से 'विकसित दिल्ली' की ओर अग्रसर होगी। इन निर्णयों से संबंधित एजेंसियों पर बेवजह का बोझ घटेगा, साथ ही निर्माण कार्य करने वाली कंपनियों को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों से दिल्ली में निर्माण कार्य नहीं हो रहे थे, या उनकी गति धीमी थी, जिसके चलते राजधानी की हालात बुरी हो गई थी। हमारी सरकार ने आते ही विकास कार्यों की गति तेज करने के प्रयास शुरू किए। हमे जानकारी मिली कि अगर निर्माण कार्यों को लेकर कुछ बदलाव कर दिए जाएं तो ये कार्य तेज गति पकड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार इसके लिए वह लगातार संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रही थीं, उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया और निर्माण करने वाली कंपनी व कॉन्ट्रेक्टरों से भी समस्याएं जानीं और लगातार समीक्षा की गई। जिसके बाद

निर्माण कार्य से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया। जो बदलाव किए गए, वे इस प्रकार हैं:-**मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ):** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इस निधि का उद्देश्य दिल्ली के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना को 2025-26 में लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के योजना विभाग को 1400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन विधायकों को अपने क्षेत्र में किसी विकास कार्य के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी, वह अब इस निधि से राशि ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 10 करोड़ रुपये तय की गई है। यह योजना स्थानीय स्तर पर विकास के लिए लचीला और गतिशील तंत्र प्रदान करेगी। इसकी विशेषता यह भी है कि प्रशासनिक विभाग, स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाएं (अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से) परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगी, जो दिल्ली मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आधारित होंगे। बड़ी बात यह भी है कि योजना विभाग प्रोजेक्ट की कुल राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम देगा और शेष 50 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। यह भुगतान कार्य की प्रगति, उपयोग प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित विभाग या एजेंसी को किया जाएगा।

विधायक निधि योजना: मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की इस योजना के अंतर्गत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाते हैं। इस योजना में अब भुगतान जारी करने के मामले में बड़ा बदलाव किया गया है। इन विकास योजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग धनराशि जारी करता है। अब पहली किश्त, यानी अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत कार्य स्वीकृत करते समय कार्यकारी एजेंसियों को जारी किया जाएगा। दूसरी किश्त यानी पहले जारी की गई 10 प्रतिशत राशि को जोड़कर निविदा राशि का 50 प्रतिशत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। इसका अर्थ यही है कि कार्य शुरू होते ही प्रोजेक्ट की कुल राशि की आधी धनराशि जारी कर दी जाएगी। बाकी 50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूरा होने पर जारी कर दी जाएगी।

शहीद उधम सिंह का बलिदान राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्मबलिदान का अनुपम उदाहरण-नायब सिंह सैनी

हिसार के गाँव बाड़ा सुलेमान का नाम उधमपुरा करने की घोषणा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका बलिदान राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्मबलिदान का अप्रतिम उदाहरण है। उधम सिंह जी ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 'जंग-ए-आजादी' के इतिहास में आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री वीरवार को सिरसा में मुख्य धाम बाबा भूमणशाह जी (संगर सरिस्ता) में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला में कम्बोज सभा को प्लॉट देने की घोषणा की। साथ ही, फतेहाबाद, कैथल और जगाधरी में प्लॉट लेने हेतु सभा द्वारा आवेदन करने उपरांत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट प्रदान किया जाएगा। इसके आलावा, मुख्यमंत्री ने हिसार के गाँव बाड़ा सुलेमान का नाम उधमपुरा करने की भी घोषणा की। बाबा भूमण शाह मुख्य धाम की भूमि पर उनके नाम से

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी चैक करवाकर इसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा, घग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा कर पूरा करवाने की घोषणा की। ओबीसी वर्ग में क्लास-1 व क्लास-2 श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे ओबीसी आयोग को अवगत करा कर लागू कराने का काम किया जाएगा। इनके अलावा, अन्य मांगों को संबंधित विभागों में फिजिबिलिटी चैक करवाने हेतु भेजा जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह जी ने असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आज के ही दिन वर्ष 1940 में शहादत पाई। उनकी कुबार्नी ने आजादी के लिए देशवासियों में एक नई जागृति पैदा की। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तथा मदन लाल ढींगड़ा जैसे अनेक देशभक्तों ने भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना और उस पर चलकर कुर्बानियां देने का इतिहास रचा।

इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद जी, श्री महेश मुनी जी, महंत गोमती दास जी, महंत सागर नाथ जी, जर्मनी के सांसद श्री राहुल कम्बोज, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल, पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री श्री करण देव कम्बोज, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक श्री दुड़ा राम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भूकंप और सुनामी से होगी बड़ी तबाही: स्वामी कैलाशपुरी महाराज

वैज्ञानिकों को चेतावनी, अगर दम है तो पृथ्वी की सीमा में ही उपग्रह छोड़कर दिखाएं

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख महाकाल कैलाशपुरी जी महाराज ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और अधिक भयंकर होंगी। उन्होंने कहा कि रूस के कामचटका द्वीप पर हाल ही में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप जैसी घटनाएं प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ का परिणाम हैं और यह सिलसिला यदि यूं ही चलता रहा तो दुनिया को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

स्वामी कैलाशपुरी महाराज ने कहा कि आज विश्व भर में वैज्ञानिक और शक्तिशाली देश प्राकृतिक संतुलन से खिलवाड़ कर रहे हैं। एटम बमों का निर्माण कर उन्हें समुद्रों में छिपाया जा रहा है, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपग्रहों के जरिए प्रयोग किए जा रहे हैं, और पृथ्वी की सीमा से बाहर जाकर वहां की संरचना से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को चेताते हुए कहा कि यदि उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास है तो वे पृथ्वी की सीमा के भीतर ही उपग्रह छोड़कर दिखाएं। पृथ्वी की सीमा को लांघना और अंतरिक्ष में जाकर उपद्रव फैलाना प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि कुदरत अपने नियमों के अनुसार चलती है। न तो उसने कभी अपने नियमों को तोड़ा है, न ही अपनी सीमाएं लांघी हैं।

लेकिन इंसान लगातार प्रकृति की सीमाओं को पार कर रहा है। कभी पहाड़ों को काटकर नगर बसाए जा रहे हैं, तो कभी जंगलों का दोहन हो रहा है। पर्यटन के नाम पर पर्वतों को खोखला किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि अब लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं।

स्वामी कैलाशपुरी ने कहा कि अब तो समुद्र में भी भूकंप आने लगे हैं, जो कि पृथ्वी की गहराइयों में हो रहे असंतुलन का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति अब हिसाब बराबर करने को तैयार है और आने वाले वर्षों में यह अपना रौद्र रूप दिखाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एटमी बम बनाने और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति नहीं रोकी गई तो प्रकृति स्वयं इन विनाश के साधनों को नष्ट कर देगी।

अमेरिका को विशेष रूप से चेताते हुए उन्होंने कहा कि यह देश अपने हथियार बेचने के लिए अन्य देशों को युद्ध में झोंक रहा है। भले ही वह व्यापार के नाम पर टैरिफ लगाए, लेकिन उसकी यह नीति अंततः उसी पर भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हथियारों की होड़ और युद्ध नीति ने मानवता को हैवानियत की ओर धकेल दिया है।

स्वामी कैलाशपुरी महाराज ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, तब-तब प्रकृति ने उसका बदला लिया है। उन्होंने सभी देशों की सरकारों और वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमें आने वाले समय में विनाशकारी परिणामों के लिए तैयार रहना होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में की लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि

11,169 करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएं वर्ष 2028-29 तक होंगी पूर्ण

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की कुल 11,169 करोड़ रुपये (लगभग) लागत वाली चार परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की।

इन परियोजनाओं में सम्मिलित हैं:-

इटारसी-नागपुर चौथी लाइन

औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण

अलुआबारी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन

डांगोपोसी-जारोली तीसरी और चौथी लाइन

बढ़ी हुई लाइन क्षमता गतिशीलता में काफी वृद्धि करेगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव संचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़ को कम करने के लिए निर्मित किए गए हैं। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नवीन भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम

परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 229 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे

से क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाने के साथ-साथ रोजगार/स्वरोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी।

परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बनाई गई है, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल संपर्कता और रसद दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्कता प्रदान करेंगी।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 2,309 गांवों तक संपर्कता बढ़ाएगी, जिनकी जनसंख्या लगभग 43.60 लाख है। ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 95.91 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) सामान की आवाजाही होगी।

रेलवे, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (16 करोड़ लीटर) कम करने और सीओ2 उत्सर्जन (515 करोड़ किलोग्राम) कम करने में मदद करेगा, जो 20 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। गोयल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माना जाता है।

पिछली सरकारों ने पंजाब वासियों और महान शहीदों को भुला दिया था-केजरीवाल

संजना भारती संवाददाता

शहीद ऊधम सिंह वाला (सुनाम)। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करके शहीदों के सपनों को साकार किया जाएगा।

यहां शहीद ऊधम सिंह वाला नगर के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत वाले परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह ने अपने देश को गुलामी की दलदल से निकालने के लिए अद्वितीय बलिदान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेना उनके लिए बहुत गर्व और शांति की बात है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम

के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान दिए ताकि समानता वाला समाज बनाया जा सके, जिससे कमजोर और दबे-कुचले वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी शहीदों के सपने अधूरे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने सरकारी खजाने की लूट की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नशे और भ्रष्टाचार के प्रतीकों के साथ पंजाब को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन राजनेताओं ने अपने निजी हितों के लिए लोगों के पैसे को बेरहमी से लूटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई थी क्योंकि पिछली सरकारों ने आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने की कभी परवाह ही नहीं की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने ही राज्य में नशे का जाल फैलाया, जिसने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया।

दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पंजाब में अब नशे की कमर टूट चुकी है, जिसके लिए राज्य सरकार की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में नशा विरोधी अभियान चलाया गया, उसकी मिसाल देश के इतिहास में नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में ईमानदार सरकार ने बदनाम और खतरनाक नशा तस्कर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कोई भी सरकार इस प्रभावशाली राजनीतिक नेता को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती थी, जो राज्य में नशे फैलाने का सूत्रधार था।

सम्पादकीय

ट्रंप का झूठ उजागर...

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर न केवल द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा की है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 'dead economy' कह कर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ट्रंप व्यापार और भू-राजनीतिक मुद्दों को दबाव की राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत का रुख इस बार बिल्कुल अलग रहाझ उसने न केवल व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से इंकार कर दिया, बल्कि रूस से संबंधों को लेकर अमेरिकी दबाव को भी ठुकरा दिया। इससे ट्रंप का यह दावा भी कमजोर हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर केवल अमेरिकी दबाव और संभावित व्यापार समझौते के लालच में रोका था। भारत के इस रुख के पीछे कई ठोस कारण हैं। दरअसल रूस भारत का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार है, जिसने परमाणु ऊर्जा, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत को लगातार सहयोग दिया है। आज भी भारत के 60% से अधिक रक्षा उपकरण रूसी मूल के हैं और सस्ते रूसी तेल ने भारत को वैश्विक ऊर्जा संकट के समय राहत दी है। अमेरिका की पैनल्टी झेलने और राष्ट्रपति की नाराजगी का जोखिम उठाकर भी भारत रूस के साथ संबंध बचाने को तैयार है, क्योंकि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का मूलभूत हिस्सा है। देखा जाये तो वैश्विक राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि भारत का यह संदेश स्पष्ट है कि वह किसी भी महाशक्ति के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलेगा। इस कदम से न केवल भारत की कूटनीतिक साख बढ़ी है, बल्कि दुनिया के अन्य मध्यम और छोटे देशों को भी यह विश्वास मिला है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में दबाव की राजनीति को चुनौती दी जा सकती है। दूसरी ओर, अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है। भारत उसके लिए Indo-Pacific रणनीति का प्रमुख साझेदार है और ट्रंप की बयानबाजी व टैरिफ की नीति इस भरोसे को कमजोर कर सकती है। यदि अमेरिका भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदार को अपमानित करता है, तो वह चीन और रूस के खिलाफ बने गठबंधनों में अपनी स्थिति कमजोर कर लेगा। ट्रंप की यह टिप्पणी उनके उस लंबे इतिहास से मेल खाती है जिसमें वे अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को केवल व्यापार और अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के नजरिए से देखते हैं। भारत के टैरिफ और रूस के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठाना एक अलग विषय है, लेकिन इन मुद्दों को हल करने का रास्ता अपमानजनक भाषा नहीं, बल्कि परिपक्व वार्ता है। भारत सरकार ने सही कहा है कि वह राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगी। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह वैश्विक शक्ति-संतुलन में किसी का मोहरा नहीं बनेगा। रूस के साथ संबंध बचाने के लिए अमेरिकी दबाव को ठुकराना केवल कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगाझ चाहे कीमत कुछ भी हो। ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाये जाने की चेतावनियों के बावजूद भारत ने न तो रूस से ऊर्जा खरीद कम की है और न ही रक्षा सहयोग में कोई कटौती की है। यह रुख बताता है कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ट्रंप का अतिरिक्त शुल्क भारत को रूस से दूर करने की कोशिश है। लेकिन यह रणनीति अब तक विफल रही है। दरअसल अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। यह संदेश चीन जैसे देशों के लिए भी है, जो रूसी तेल के बड़े खरीददार हैं। भारत का रूस के साथ संबंध मजबूत रखना अमेरिका के लिए चिंता का विषय है इसलिए वह चाहता है कि भारत Quad में मजबूत हो मगर Indo-Pacific रणनीति के तहत रूस से दूरी बनाए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत किसी के दबाव में अपने रणनीतिक निर्णय नहीं बदलेगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं हो पाने का बड़ा कारण यही है कि भारत ने कृषि, डेयरी और टैरिफ में अपनी शर्तों से समझौता करने से इंकार कर दिया है। साथ ही भारत ने दिखा दिया है कि रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व रखते हैं। देखा जाये तो अमेरिका के आगे नहीं झुक कर भारत की वैश्विक स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है।

जयंती

पुरुषोत्तम दास टंडन

जन्म-1 अगस्त, 1882, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश; मृत्यु-1 जुलाई, 1962) आधुनिक भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में से एक थे। वे 'राजर्षि' के नाम से भी विख्यात थे। उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में प्रारम्भ किया था। हिन्दी को आगे बढ़ाने और इसे राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए पुरुषोत्तम दास जी ने काफी प्रयास किये थे। वे हिन्दी को देश की आजादी के पहले आजादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आजादी मिल जाने के बाद आजादी को बनाये रखने का। वर्ष 1950 में वे 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नयी चेतना, नयी लहर, नयी क्रान्ति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया है। वर्ष 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया था।

पुण्यतिथि

बाल गंगाधर तिलक

जन्म-23 जुलाई, 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र; मृत्यु-1 अगस्त, 1920, मुंबई) विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। उन्होंने 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना सन 1914 ई. में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन 1916 में मुहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आजादी के लिए संघर्ष में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रावधान था।

कल मिलेंगे

राहुल एक बार बीमार होने पर अकेले अस्पताल गया...
डाक्टर ने उसे सूई लगाई और कहा-
चिंता मत करो, तुम्हें लेने तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे..
राहुल-लेकिन वो तो सालों पहले मर चुके हैं.
डाक्टर-मुझे पता है, तुम बस इंतजार करो.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

अमेरिका के टैरिफ अटैक से प्रभावित होंगे भारतीय निर्यात, लेकिन लांग टर्म में कारोबारी हित रहेंगे अछूते!

फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्द्धन अग्रवाल ने ट्रंप के बयान पर निराशा जताते हुए कहा है कि, "इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम का हमारे एक्सपोर्ट्स पर साफ तौर पर असर पड़ेगा। उम्मीद है कि ज्यादा टैरिफ का दौर छोटा ही रहेगा और दोनों पक्षों के बीच एक स्थायी व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा।" वहीं, पीएचडीसीसीआई के प्रेसिडेंट हेमंत जैन ने कहा है कि, "समय आ गया है कि इंडियन इंडस्ट्री क्वॉलिटी और कॉम्पिटीटिवनेस के साथ खड़ी हो

-कमलेश पांडेय

लीजिए, अंततोगत्वा अमेरिका ने भारत पर अपना टैरिफ बम फोड़ ही दिया। लेकिन अब भारत क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इसपर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि गत बुद्धवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय चीजों पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने का पुनः ऐलान किया। हालांकि, चतुराई पूर्वक ट्रंप ने भारत को 'दोस्त' बताते हुए निज सोशल मीडिया साइट 'सोशल ट्रूथ' पर किये गए अपने पोस्ट में लिखा है कि यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा।

वहीं, अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि ट्रंप का यह टैरिफ पहले से लागू 10% शुल्क के अतिरिक्त होगा या उसमें ही समाहित होगा। इसके अलावा, भारत की रूसी मित्रता के लिए जो अमेरिकी जुमार्ना लगेगा, वह कितना होगा। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले गत 2 अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर 10% टैरिफ लगाया था, जिसे पहले 90 दिनों तक और फिर बाद में 1 अगस्त तक टाल दिया था।

वहीं, इस बार ट्रंप ने यह ऐलान भी किया कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुमार्ना भी लगाएंगे। हालांकि यह जुमार्ना कितना होगा, उन्होंने यह अभी साफ नहीं किया। बता दें कि ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान ऐसे समय किया है, जब कारोबारी समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल 25 अगस्त को भारत आने वाला है। इसलिए जानकार ट्रंप के इस ऐलान को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारत क्या अमेरिका के टैरिफ के समक्ष घुटने टेक देगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

ट्रंप के मुताबिक, भारत और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन उसके साथ बहुत कम ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत ऊंचे टैरिफ लगा रखे है। भारत की गैर-आर्थिक कारोबारी बाधाएं दुनिया में सबसे कठोर है। यही नहीं, जब पूरी दुनिया रूस को यूक्रेन में नरसंहार रोकने के लिए कह रही थी, भारत ने तब भी उससे बड़ी मात्रा में हथियार और तेल खरीदा। इसके अलावा चीन के साथ वह सबसे बड़े खरीदार हैं। हालांकि, ट्रंप यह भूल गए कि भारत रूस से बार बार यह भी कहता रहा है कि यह युद्ध नहीं, बुद्ध का समय है। इसलिए भारत पर थोपे गए इस अमेरिकी टैरिफ के खास मायने हैं, जिसे समझे जाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि भारत से सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को ही होता है। गत जून तक में यूएसए को 829.8 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। जबकि साल 2025 में करीब 91 नए टैरिफ दर से इस निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे भारत के ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स ऐंड जूलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फार्मा सेक्टरों की चीजें अमेरिका में महंगी होंगी।

हालांकि, बांग्लादेश पर 35%, थाइलैंड पर 36%, कंबोडिया पर 36%, जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों पर ज्यादा टैरिफ से कम आंच आएगी। वहीं, जहां तक शेयर बाजार में असर का सवाल है तो चुनौती वाले सेक्टरों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर असर दिख सकता है। हालांकि इस जवाबी टैरिफ की आशंका पहले से थी। इसलिए कुछ उतार-चढ़ाव के बाद यह स्टेबल हो सकता है, क्योंकि भारतीय इकॉनमी मजबूत स्थिति में है। इसलिए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि, ""द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है सरकार उसके असर का स्टडी कर रही है। भारत और अमेरिका निष्पक्ष संतुलित परस्पर लाभप्रद व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे है। सरकार राष्ट्रीय हितो की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।" वहीं, जानकारों का मानना है कि ट्रंप के ऐलान के बाद भी टैरिफ घटने का चांस है, क्योंकि साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि, इस बातचीत के बीच में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है, उससे निर्यात पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए उद्योग संगठनों ने यह चिंता जताई है। उल्लेखनीय है कि व्यापार समझौते पर बातचीत के छठे दौर के लिए अमेरिकी अधिकारियों का दल 25 अगस्त को भारत आने वाला है। जबकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रंप ने जो कुछ कहा है, उसमें पेनाल्टी सहित कुछ चीजें साफ नहीं है। इसलिए द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत जारी रहेगी। इस बीच मिनी ट्रेड डील का प्रयास भी हो रहा है। यह डील होने पर इसकी शर्तों के मुताबिक टैरिफ लगेगा। इसकी संभावना बनी हुई है।'

वहीं, निर्यातकों के संगठन एफआईईओ के डायरेक्टर जनरल डॉ. अजय सहाय ने कहा है कि, "ट्रंप के कदम से अनिश्चितता बढ़ गई है। कितनी पेनाल्टी लगेगी, यह साफ होने तक भारतीय निर्यातक और अमेरिकी आयातक न तो लैंडेड कॉस्ट का अंदाजा लगा पाएंगे, न ही यह आकलन कर पाएंगे कि टैरिफ के बोझ से किस तरह निपटा जाएगा। इस अनिश्चितता से सप्लाई चेन प्लानिंग और प्राइसिंग की रणनीति प्रभावित होगी।"

वहीं, फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्द्धन अग्रवाल ने ट्रंप के बयान पर निराशा जताते हुए कहा है कि, "इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम का हमारे एक्सपोर्ट्स पर साफ तौर पर असर पड़ेगा। उम्मीद है कि ज्यादा टैरिफ का दौर छोटा ही रहेगा और दोनों पक्षों के बीच एक स्थायी व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा।" वहीं, पीएचडीसीसीआई के प्रेसिडेंट हेमंत जैन ने कहा है कि, "समय आ गया है कि इंडियन इंडस्ट्री क्वॉलिटी और कॉम्पिटीटिवनेस के साथ खड़ी हो। चीन और वियतनाम पर इसी तरह के टैरिफ लगने के साथ भारत को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, विविधता से भरे मार्केट शेयर और भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के रूप में मजबूत पोजिशनिंग से फायदा होगा।"

सवाल है कि आखिर अमेरिकी टैरिफ का किस तरह का असर दिखेगा? तो जवाब होगा कि रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कपड़ा और दवा उद्योगों का मामला ज्यादा अहम है। क्योंकि अमेरिका को कुल निर्यात में इनका हिस्सा 40% से ज्यादा है। वर्ष 2024 में भारत से 21.5 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, 12.7 बिलियन डॉलर की दवाएं, 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रत्न-आभूषण और 8 बिलियन डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स सहित टेक्सटाइल्स अमेरिका भेजे गए। हालांकि भारत अकेला नहीं है जिस पर नया रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ ठोका गया है, बल्कि लगभग 90 देशों पर अमेरिका ने जवाबी टैरिफ लगाया है। इसमें बांग्लादेश पर 35%, थाईलैंड पर 36%, कंबोडिया पर 36% और इंडोनेशिया पर 32% का टैरिफ लगाया गया है। इसलिए भारत के लिए सब्र की बात यह है कि उसके जैसे अन्य मुख्य कारोबारी प्रतिद्वंद्वी देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, जिसको देखते हुए तुलनात्मक रूप से भारत पर कुछ मामलों में कम आंच आएगी। इससे कुछ रणनीतिक बातें भी अब साफ होने में मदद मिलेगी।

ऐसा इसलिए कि वैश्विक दुनियादारी में यह आम अवधारणा है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। इसके अलावा, अमेरिका से दोस्ती को खल से प्रीति करार दिया जाता है। तभी तो कभी चीन के खिलाफ भारत को अपना मजबूत हिन्द महासागर सहयोगी बताने वाला अमेरिका अब भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दुश्मनी के हर कोने को खंगाल लेना चाहते हैं, ताकि वैश्विक आर्थिक और सैन्य रेस में तेजी से फर्राटे भर रहे भारत को पछाड़ा जा सके।

हैरतअंगेज तो यह है कि इसके लिए अमेरिका ने गद्दार पाकिस्तान और महत्वाकांक्षी चीन की हर शर्तें स्वीकार कर लीं, ताकि रूस का सहयोग करके अमेरिकी-यूरोपीय अरमानों को कुचलने वाले भारत को काबू में किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ बताते हैं कि रूस के सदाबहार सहयोगी चीन से अब अमेरिका को उतना खतरा नहीं है, जितना कि ग्लोबल साउथ के पैरोकार भारत की मौजूदा और भविष्य की योजनाओं से है।

समझा जाता है कि जैसे कभी रूस के खिलाफ चीन को सहयोग करने वाला अमेरिका चीनी मनमानी से परेशान होकर भारत को मदद करने लगा, फिर भारत की मनमानी से परेशान होकर पाकिस्तान को मदद करने लगा, फिर पाकिस्तान की मनमानी को काबू में रखने के लिए बंगलादेश की मदद करने लगा, उसके भारतीय उपमहाद्वीप में रणनीतिक मायने हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अरब देशों में इजरायल की मदद के रणनीतिक मकसद हैं, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के रणनीतिक फायदे हैं, चीन के खिलाफ ताइवान को सहयोग देने के रणनीतिकार लाभ हैं। चूंकि यह सभी कार्य अमेरिकी प्रशासन अपने हथियार लॉबी की योजनाओं के मुताबिक करता है, इसलिए उसे इन खुराफातों के लिए कभी धन की कमी नहीं पड़ती। जबकि उसकी इन हरामखोर नीतियों से प्रभावित देश आपसी प्रतिरोपित लड़ाई-झगड़े में बर्बाद होते रहते हैं। इससे वे अमेरिकी डॉलर मदद और हथियार सप्लाई रैकेट के सहज शिकार हो जाते हैं। भारत इसे बखूबी समझता है। इसलिए कभी भारत विरोधी रहे अमेरिका के साथ नई दोस्ती के कदम बढ़ाने के साथ-साथ भारत ने फूंक फूंक कर हर निर्णय लिए, ताकि उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित नहीं हो।

चूंकि भारत ने रूस के साथ दोस्ती नहीं छोड़ी, चीन के साथ नियंत्रित पंगा लिया, अमेरिका व यूरोप के बीच कारोबारी दूरी बढ़ाने के लिए अमेरिका के बजाय फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली व यूरोपीय संघ को तवज्जो दिया, अरब देशों में इजरायल, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों को प्रमुखता दी, अफ्रीकी व दक्षिण अमेरिकी देशों से प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाए, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से अपने हितों के अनुरूप दोस्ती गांठे। जो अमेरिका-चीन को नागवार गुजरी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

एआई का विस्तार या नौकरी का संकुचन एक बड़ी चुनौती

टीसीएस का दावा है कि छंटनी का निर्णय भविष्य की जरूरतों के अनुसार संगठन को ढालने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का ध्यान एआई में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहक अनुभव सुधार और कार्यबल मॉडल के पुनर्गठन पर केंद्रित है। हालांकि, यह तर्क उन हजारों कर्मचारियों की व्यथा को शांत नहीं कर सकता जिनकी आजीविका पर इसका सीधा प्रहार हुआ है

-ललित गर्ग

भारत जैसे युवाओं वाले और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में तकनीकी विकास के प्रति उत्साह हमेशा गहरा रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकें समाज, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव की सारथि बनी हैं। हर वर्ग और क्षेत्र ने इस परिवर्तन को आशा एवं सकारात्मकता के साथ अपनाया है, इस उम्मीद में कि तकनीकी तरक्की के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन हाल ही में आईटी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसे बड़ा झटका दिया है। निस्संदेह, छंटनी का यह फैसला आईटी क्षेत्र में आसन्न संकट की आहट को ही दशार्ता है। छंटनी बाबत टीसीएस की दलील है कि इन नौकरियों में कटौती कौशल की कमी और अपने विकसित होते व्यावसायिक मॉडल में कुछ कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने में असमर्थता के चलते की गई है। हालांकि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि इस कदम के पीछे एआई से प्रेरित उत्पादकता वृद्धि नहीं है। यह संख्या कंपनी के कुल कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत है, और मुख्यतः मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, एमेजोन ने 30,000 सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों को एआई की मदद से मात्र छह महीनों में अपग्रेड किया, जो कार्य सामान्यतः डेवलपर्स को एक वर्ष लगता। इससे कंपनी को लगभग 250 मिलियन डॉलर की बचत हुई। इसी प्रकार, माइक्रोसोफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में कोडिंग का 20 से 50 प्रतिशत कार्य एआई से कराया जा रहा है। भारत में एआई का प्रसार अभी अमेरिका या यूरोप की तुलना में सीमित है, लेकिन इसकी गति तीव्र है। देश के स्टार्टअप और आईटी क्षेत्र में छंटनियों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल वर्ष 2025 के शुरूआती पांच महीनों में भारत में 3600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जिसमें एआई आधारित लागत नियंत्रण एक प्रमुख कारण रहा। यह स्पष्ट करता है कि एआई के कारण दोहराव वाले कार्यों की उपयोगिता घट रही है और उनकी जगह स्मार्ट तकनीक ले रही है। मौजूदा समय में यह कदम लागत-अनुकूलन पहलों के चलते अन्य आईटी सेवा कंपनियों में भी छंटनी को बढ़ावा दे सकता है। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारोबार के नियमों में मौलिक बदलाव के चलते, भविष्य के लिये तैयार रहना हर व्यावसायिक उद्यम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। इस नई हकीकत को देखते हुए, अनेक सवाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाले बनकर उभर रहे हैं कि क्या यह तकनीकी बदलाव अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की कीमत पर होना चाहिए? एआई युग में नौकरी की अनिश्चितता क्या तकनीक विकास के नाम पर विस्थापन नहीं है? छंटनी की चपेट में युवाओं का भविष्य क्या तकनीकी प्रगति के नाम पर मानव श्रम पर आघात नहीं है? क्या स्मार्ट मशीनें के दौर में भारत में रोजगार को नई चुनौती और इंसानों को हताशा में धकेलना नहीं है? एआई का विस्तार यानी नौकरी का संकुचन क्या भारत के लिए बड़ी चेतावनी की घड़ी बन रहा है?

इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी का संकट किसी से छिपा नहीं है। देश में श्रमबल का कौशल विकास धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में आईटी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन टीसीएस के इस फैसले से आईटी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे उन लाखों छात्रों और डिग्री लेकर निकल रहे उत्साही इंजीनियरों में निराशा व्याप्त होगी। भारत में बढ़ता रोजगार संकट केंद्र सरकार से निरंतर हस्तक्षेप की मांग करता है। हाल ही में हरियाणा में हुई एक परीक्षा में लाखों युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि रोजगार की मांग कितनी व्यापक और अवसर कितने सीमित हैं। देश ही नहीं, दुनिया में रोजगार का संकुचन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गोल्डमैन सोच्स की रिपोर्ट के अनुसार, एआई और ऑटोमेशन के चलते दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच का आकलन है कि 2030 तक 92 मिलियन नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन उसी अवधि में 170 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह एक दोधारी तलवार है, जो बदलेगा, बचेगा; जो रुकेगा, वो हाशिए पर जाएगा।

टीसीएस का दावा है कि छंटनी का निर्णय भविष्य की जरूरतों के अनुसार संगठन को ढालने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का ध्यान एआई में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहक अनुभव सुधार और कार्यबल मॉडल के पुनर्गठन पर केंद्रित है। हालांकि, यह तर्क उन हजारों कर्मचारियों की व्यथा को शांत नहीं कर सकता जिनकी आजीविका पर इसका सीधा प्रहार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल कंपनी के भीतर बल्कि समूचे आईटी क्षेत्र में आशंका, आक्रोश एवं अनिश्चितता का माहौल बन गया है। खासकर युवाओं और आईटी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह एक मानसिक झटका है। तकनीकी शिक्षा में दाखिले बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। यह असंतुलन देश की सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि विश्व स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत नौकरियां एआई के कारण जोखिम में हैं। भारत में अनुमान है कि 2025 तक 12-18 मिलियन नौकरियां एआई आधारित ऑटोमेशन के चलते प्रभावित हो सकती हैं, विशेषकर आईटी और बीपीओ क्षेत्रों में। एटेमबर्ग के संस्थापक के अनुसार, भारत में 40-50 प्रतिशत व्हाइट कॉलर नौकरियां एआइ से प्रभावित होने के कगार पर हैं, जिससे देश के मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिरता को गहरा झटका लग सकता है।

निश्चित तौर पर एआई और तकनीकी बदलाव अपरिहार्य हैं। सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? इसके लिए तीन प्रमुख कदम जरूरी हैं, पहला पुनःकौशल और सतत शिक्षा यानी कार्यबल को भविष्य के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना होगा। दूसरा नीतिगत समर्थन यानी सरकार को एआई नीति, डिजिटल समावेशन और श्रमिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने होंगे।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

कुछ नहीं मिलने वाला है...भारत पर टैरिफ लगाते ही चीन ने ट्रंप पर कर डाला तगड़ा ऐलान

(एजेन्सी)।

एक तरफ अमेरिका की तरफ से सात भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सरकार की ओर से भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाकर सोच रहे हो कि उन्होंने भारत को चोट दी है। लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ताकत बता दी है। ट्रंप की टैरिफ वाली दवाब नीति पर चीन का बयान सामने आया है। चीन ने अमेरिका के इस सुझाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यदि चीन रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो वह टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। चीन ने कहा कि जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा।

पहले चेतावनी अमेरिका की ओर से दी गई। उसकेबाद चीन की ओर से इस पर जवाब सामने आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिकी सुझाव के जवाब में कि यदि चीन रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो वह टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा वाले बयान पर कहा कि चीन हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चीनी प्रवक्ता ने साफ किया कि टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता। जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा।

अमेरिका की तरफ से 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने को लेकर भारत एक्शन में आ गया है। ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ पर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए भारत सरकार ने कहा कि हमने द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है। सरकार इसके परिणामों का अध्ययन कर रही है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके अलावा भारत में ट्रंप के फैसले को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। यानी की सरकार एक्शन मोड में आ गई है।

ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चीन और रूस के साथ व्यापार करने पर नाराजगी जताई है।

सोना 500 रुपये टूटा, चांदी में 2,000 रुपये की गिरावट

(एजेन्सी)।

राष्ट्रीय राजधानी के सरार्फा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमत 500 रुपये टूटकर 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। रुपये में मजबूती के कारण कीमती धातु की कीमत पर अंकुश लगा। अखिल भारतीय सरार्फा संघ ने यह जानकारी दी। बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 98,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 400 रुपये टूटकर 97,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रहा। पिछले सत्र में यह 650 रुपये बढ़कर 98,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा, बृहस्पतिवार को चांदी की कीमतें 2,000 रुपये टूटकर 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रही। बुधवार को यह 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कच्चे तेल की कम कीमतों और रिजर्व बैंक के संदिग्ध हस्तक्षेप के बीच, रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अबतक के सबसे निचले स्तर से 22 पैसे सुधरकर 87.58 (अस्थायी) पर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क और रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर जुमार्ना लगाने की घोषणा के बाद रुपया बुधवार को अबतक के सबसे निचले स्तर पर चला गया था।

अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क की घोषणा के बाद बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.80 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि सकारात्मक अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया। इससे सरार्फा कीमतों पर दबाव बढ़ा। उन्होंने कहा, नवीनतम जीडीपी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, जिससे ब्याज दरों के दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

अनुराग की क्राइम गाथा 19 सितंबर को होगी रिलीज

(एजेन्सी)।

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आगामी नाट्य रिलीज "निशानची" का पहला लुक जारी कर दिया है, और यह अनुराग कश्यप के प्रशंसकों की उम्मीदों के मुताबिक ही धमाकेदार और दिलचस्प है। 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह फिल्म ऐश्वर्या ठाकरे के अभिनय करियर की शुरूआत है, जो इस रोमांचक अपराध गाथा में एक चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका निभा रही हैं।

अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित और प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और कश्यप द्वारा सह-लिखित, निशानची का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से किया है। यह फिल्म ऐश्वर्या ठाकरे के प्रभावशाली अभिनय करियर की शुरूआत को दशार्ती है, जहाँ उन्होंने दोहरी भूमिका में एक गतिशील प्रदर्शन दिया है। इसमें उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी हैं, जो प्रमुख सहायक भूमिकाएँ निभा रहे हैं। कश्यप ने जून 2025 में इस फिल्म की घोषणा की थी। 'निशानची' का अनोखा, रंगीन फर्स्ट लुक कच्ची, जमीनी कहानी को दशार्ता है, जैसा कि पहले 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'गुलाल', 'मुक्केबाज' जैसी फिल्मों में देखा गया है। दर्शकों को मुख्यधारा के सिनेमाई अंदाज के साथ-साथ यथार्थवाद का भी आभास होता है। रोमांच से भरपूर यह क्राइम-ड्रामा अंडरवर्ल्ड पर आधारित एक सच्चा मसाला एंटरटेनर होने का वादा करता है। आगामी एक्शन से भरपूर यह फिल्म दो भाइयों की कहानी है—एक-दूसरे के प्रतिरूप, फिर भी दुनिया से अलग, जिनके फैसले उनके भाग्य को आकार देते हैं।

मूल रूप से, 'निशानची' नवोदित ऐश्वर्या की एक आकर्षक दोहरी भूमिका के बारे में है—जुड़वाँ भाई बिल्कुल अलग-अलग ज़िंदगी जीते हैं, एक ऐसे तूफान में फँस जाते हैं जो फूटने को तैयार है। अनोखा रेट्रो-स्टाइल पोस्टर एक बहुस्तरीय, बेबाक नाटकीय परिदृश्य का रूपक भी है जहाँ प्यार, बदला और नियति आपस में टकराते हैं। फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा जैसे दमदार कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह गंभीर और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली कहानी अजय राय और रंजन सिंह द्वारा जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से निर्मित की गई है और प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप द्वारा लिखित है।

शुभमन ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड

(एजेन्सी)। इंडिया और इंग्लैंड के बीच द ओवल में आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर का 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड था बतौर कप्तान एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। इंग्लैंड के खिलाफ 11 रन बनाते ही गिल ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया और वह भारत के नंबर-1 कप्तान बन गए हैं। बता दें कि, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही। 38 रन के स्कोर पर भारत को दो झटके लग गए। जहां यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल पर काफी दबाव था। हालांकि, महज 11 रन बनाते ही उन्होंने बतौर कप्तान एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सुनील गावस्कर ने 1978/79 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 मैचों की 9 पारियों में 91.50 की औसत के साथ 732 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 शतक जड़े थे। वहीं तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में रेड हॉट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अब तक इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं खबर लिखे जाने तक गिल 23 गेंदों पर 15 रन बना चुके हैं। उनके नाम अब इस सीरीज में 737 रन हो गए हैं। फिलहाल, अब उनकी नजरें बतौर सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड पर हैं।

प्रो कबड्डी लीग का फुल शेड्यूल जारी

(एजेन्सी)। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन की शुरूआत 29 अगस्त से होने जा रहा है। नए सीजन का पहला मैच तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच खेला जाएगा। जबकि इसी दिन दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स की टीम पुनेरी पलटन को चुनौती देगी। 2025 के अभियान में विशाखापत्तनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में 12 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। 30 अगस्त को घरेलू टीम तेलुगु टाइटंस एक बार फिर मैट पर उतरेगी। इस बार शाम के पहले मैच में यूपी योद्धा से उसका सामना होगा। इसके बाद यू मुंबई की टीम गुजरात जायंट्स को चुनौती देगी। 12 सितंबर से जयपुर के इंडोर हॉल, एसएमएस स्टेडियम में पीकेएल के मुकाबले होंगे। यहां पहले दिन दो बार की चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच रोमांचक मैच खेला जाएगा, जिसके बाद तमिल थलाइवाज और बंगाल वॉरियर्स के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीजन का लीग चरण 13 अक्तूबर से दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने चरण पर होगा। पटना पाइरेट्स का सामना हरियाणा स्टीलर्स से होगा, जबकि यू मुंबा की टीम यूपी योद्धा के साथ होगी। लीग राउंड ट्रिपल हेडर के साथ समाप्त होंगे। प्लेऑफ के शेड्यूल की घोषणा बाद में होगी।

मान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं को नया सशक्तिकरण, जन-केंद्रित नीतियों का निरंतर क्रियान्वयन: डॉ. बलजीत कौर

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त, समर्थ एवं जनहितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के तहत पूरे पंजाब में 5000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को 30 सितंबर 2025 से पहले भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग द्वारा 23 जुलाई से 15 अगस्त तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पदोन्नति, तबादले/समायोजन तथा तरस के आधार पर नियुक्तियों हेतु विशेष कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अंतर्गत, जिन कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए 1 अगस्त से 8 अगस्त तक प्रक्रिया चलाई जाएगी, जबकि तबादले/समायोजन 15 अगस्त से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। डॉ.बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि यह पहली बार है जब सेवा के दौरान स्थायी रूप से अपंग हो गए या जानलेवा बीमारी के कारण असमर्थ हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के आश्रितों को सरकारी नौकरी का अवसर दिया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण, सुरक्षा और उत्साहवर्धन के लिए पंजाब सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय सहानुभूति, न्याय और जिम्मेदार प्रबंधन के प्रतीक हैं। सरकार अपने अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सेवा का सदैव सम्मान करती है और उनके अधिकारों की पूरी रक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के विज्ञापन 22 अगस्त को जारी किए जाएंगे, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर होगी। भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूर्णतया योग्यता (मेरिट) और पारदर्शिता के आधार पर की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या भेदभाव की कोई संभावना नहीं रहेगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से पंजाब सरकार न केवल आंगनवाड़ी सेवाओं को, बल्कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने हेतु जमीनी स्तर पर परिवर्तन ला रही है। ये कदम केवल भर्तियों या तबादलों तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं, जो पंजाब को न्यायसंगत, सहानुभूतिशील और विकसित समाज की ओर ले जाते हैं।

खानपुर प्रखंड के मसीना बीआरसी भवन परिसर में प्रखंड शिक्षा पदा. की सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

■ विदाई होने पर भावुक हुई लक्ष्मी कुमारी ■ आप की निष्ठा पूर्वक कार्यकाल यादगार रहेगी-बीडीओ

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी की सेवानिवृत होने पर आज बी.आर.सी. भवन मसीना परिसर में विदाई सह सम्मान समाहरोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा, बीपीआरओ संजीव कुमार, राजस्व पदाधिकारी ऋषि कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर प्रभात रंजन, संगीता मिश्रा ने संयुक्त रूप दीप प्रज्वलित कर किया। उदघाटन के उपरांत सेवा निवृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी को पाग, चादर, माला, बुके के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उपस्थित लोगो को सम्बोधित करते प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा ने कहा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत लक्ष्मी कुमारी ने निष्ठां के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वाहन किया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाय कम होंगी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में प्रखंड के सभी विद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलजुलकर शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधारने में जुटी रही। शिक्षक नेता महेश प्रसाद यादव ने सम्बोधित करते हुए कहा प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक इनके कार्यकाल को सदा याद करत रहेंगे। इस दौरान संगीत शिक्षक श्रुति राय, ज्वाला राय, तरमीम अख्तर, श्रेया कर्ण आदि ने मनमोहक स्वागत गीत, संगीत और विदाई गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय मध्य विद्यालय सिरोपट्टी के प्रधानाध्यापक अमोद कुमार ने किया जबकि संचालन प्रधान शिक्षक लाल बाबू ने किया। कार्यक्रम को श्याम कुमार पांडेय, राजीव कुमार झा, शैलेन्द्र कुमार झा, अशोक कुमार, आशिफ वकील सहित दर्जनों शिक्षकों ने संबोधित किया। मौके पर शिक्षक पंकज कुमार चौधरी, शिवशंकर चौधरी, बिपिन कुमार ठाकुर, रुदल कुमार, परमानंद सहनी, लेखपाल ज्योति कुमारी, प्रखंड संसाधन सेवी शिव कुमार, बीआरपी हरिप्यारे सिंह, सुनील कुमार, रामप्रवेश राय, गिरीशचंद्र यादव, अरविंद कुमार, रेखा कुमारी, डेटा इंट्री ऑपरेटर अनुज कुमार, शिक्षा सेवक कृष्ण कुमार महतो, तालीमी मरकज के मो सईद सहित सैकड़ों बच्चें, अभिभावक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में फार्मा यूनिट से चल रही अवैध ट्रामाडोल सप्लाई चेन का पर्दाफाश; छह व्यक्ति गिरफ्तार

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर चलाई जा रही नशा विरोधी मुहिम के तहत, पंजाब पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर में 35 गोलियां की एक छोटी सी बरामदगी से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित निर्माण यूनिट तक फैले ट्रामाडोल की अवैध सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है।

यह कार्रवाई ट्रॉमाडोल की 35 गोलियां की बरामदगी और अमृतसर के थाना ए-डिवीजन क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के तहत स्थानीय तस्कर रविंदर सिंह उर्फ निका की गिरफ्तारी के बाद की गई बारीकी से जांच के फलस्वरूप की गई है। पुलिस ने मात्र 15 दिनों में ट्रामाडोल की 74,465 गोलियाँ, अल्प्राजोलम की 50 गोलियाँ और ट्रामाडोल का 325 किलोग्राम कच्चा माल बरामद किया है।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मामले से संबंधित खुलासों और छापों के आधार पर एक केमिस्ट, वितरक और लूसेंट बायोटेक लिमिटेड के प्लांट प्रमुख समेत कुल छह गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। गिरफ़्तार व्यक्तियों की पहचान लूसेंट बायोटेक लिमिटेड, रुड़की के प्लांट मैनेजर हरी किशोर और रिकाल लाइफसाइंसेज, रुड़की के मालिक-कम-पार्टनर बिक्रम के रूप में हुई है। अन्य गिरफ़्तार व्यक्तियों में मनीष कुमार अरोड़ा, पूरन जाटव और कथूनंगल स्थित मेडिकल स्टोर के मालिक कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा शामिल हैं। डीजीपी यादव ने बताया कि जब्त की गईं "ट्राकेमी-100" ट्रामाडोल की पट्टियाँ, जिन पर केवल सरकारी आपूर्ति-बिक्री के लिए नहीं छपा हुआ है, यह दर्शाती है कि सरकारी मेडिकल स्टॉक की अवैध तरीके से हेराफेरी की गई है, जो कि अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख फार्मा कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें सील कर दिया गया है और उनके रिकॉर्डों की गहन जांच की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच अभी भी जारी है।

पुलिस कमिश्नर अमृतसर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों की एक संयुक्त टीम ने हरिद्वार के रुड़की स्थित फार्मा कंपनियों पर छापेमारी की, जहाँ से बिना लेबल की ट्रामाडोल की 4,130 गोलियाँ और 325 किलोग्राम अवैध कच्चा माल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी पूर्व में जब्त की गईं 70,335 गोलियों और 7.69 लाख रुपये की ड्रग मनी के अतिरिक्त है। पूछताछ के दौरान आरोपी हरी किशोर ने स्वीकार किया कि उसने निर्माण यूनिट में ट्रामाडोल टैबलेट 'ट्राकेमी-100' की पट्टियों पर केवल सरकारी आपूर्ति-बिक्री के लिए नहीं छपवाया था और अब उस मुहर को नष्ट कर दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि एक अन्य फार्मा कंपनी के लिए तैयार की गई ट्रामाडोल टैबलेट की अवैध सप्लाई रिकाल लाइफसाइंसेज, रुड़की को बेची गई थी। उन्होंने बताया कि इस फार्मा ओपिओइड सप्लाई नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।

इस संबंध में थाना ए-डिवीजन, अमृतसर में एफआईआर नंबर 108 दिनांक 16-07-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 27(ए), 29 और 31 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

किसानों को मक्का की टिकाऊ खेती पर मिला प्रशिक्षण, एथेनॉल उद्योगों के लिए उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया जोर

कुंजपुरा गांव में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में 50 से अधिक किसानों ने लिया भाग

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), लुधियाना एवं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा मक्का की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एथेनॉल उद्योगों के कैचमेंट क्षेत्रों में मक्का उत्पादन में वृद्धि परियोजना के अंतर्गत करनाल जिले के कुंजपुरा गांव में संपन्न हुआ, जिसमें 50 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मक्का की उन्नत किस्मों, पर्यावरण-अनुकूल खेती विधियों और टिकाऊ कृषि तकनीकों से अवगत कराना था, जिससे वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रमुख डॉ. एस.एल. जाट ने मक्का की वैश्विक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अमेरिका, चीन और ब्राजील जैसे देशों में मक्का का भारी उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, अकेले अमेरिका का मक्का उत्पादन 390 मिलियन टन से अधिक है, जो भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है। उन्होंने खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व प्रबंधन को मक्का की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया।

सीसीएसएचएयू करनाल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. हरमिंदर ने मक्का की बीमारियों की पहचान और उनके एकीकृत प्रबंधन उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे राज्यों में मक्का की खेती जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपयुक्त विकल्प है। आईआईएमआर के निदेशक डॉ. एच.एस. जाट ने अपने संदेश में कहा कि, भारत में मक्का का वार्षिक उत्पादन लगभग 42 मिलियन टन है, लेकिन एथेनॉल की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना आवश्यक है। रिसर्च एसोसिएट डॉ. मनीष ककरालिया ने बताया कि मक्का की खेती कम सिंचाई और कम रासायनिक खादों में संभव है, जिससे खेती की लागत घटती है और भूमि की उर्वरता बनी रहती है। उन्होंने मक्का को जल संरक्षण और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी बताया।

कार्यक्रम में ग्रो इंडिगो कंपनी के कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रो इंडिगो के प्रतिनिधि नवीन कुमार ने बताया कि मक्का की खेती कार्बन प्रबंधन में सहायक है और इससे किसानों को वार्षिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। प्रशिक्षण सत्र में आईआईएमआर के यंग प्रोफेशनल शुभम सैनी ने किसानों के साथ संवाद किया और उन्हें उन्नत तकनीकों तथा सतत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को टिकाऊ और लाभकारी खेती के लिए प्रेरित करने वाला साबित हुआ, जिससे न केवल मक्का की उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिए बांडी नदी की दीवार बनाने के निर्देश

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बांडी की टूटी दीवार को जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि रामनगर स्कूल के बाहर नाला व नाली निर्माण हो ताकि सड़कों पर पानी जमा न हो। उन्होंने वरूण सागर रोड स्थित आदित्य नगर व डिफेंस कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। वहां पुलिया बनाने पर स्थानीय नागरिकों ने श्री देवनानी का अभिनंदन किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने गुरूवार को अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बांडी नदी का अवलोकन कर एडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी की टूटी दीवार तुरंत बनाई जाए। इसी तरह रामनगर स्कूल के बार नाला व नाली निर्माण भी जल्द कराया जाए ताकि सड़कों पर एवं स्कूल में पानी जमा न हो। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। श्री देवनानी ने वरूण सागर रोड़ स्थित आदित्य कॉलोनी एवं डिफेंस कॉलोनी का निरीक्षण किया। इन दोनों कॉलोनियों में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलियाओं की जगह नई एवं मजबूत पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है। श्री देवनानी का वहां पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने अभिनंदन किया।

इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि हम प्राथमिकता के साथ क्षेत्र का विकास का रहे है। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पुलिया, सड़क व अन्य सार्वजनिक इमारतों को नुकसान हुआ है। इन सभी को दुरूस्त किया जा रहा है। एडीए, नगर निगम व पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। प्राथमिकता तय कर सड़क, नाला, नाली व दीवारों की मरम्मत व नवनिर्माण किया जाए। किसी भी क्षेत्र में समस्या नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बड़ी सड़कों के साथ ही अंदरूनी सड़कों की भी मरम्मत होगी।

मुख्यमंत्री ने रबी फसल-2025 के नुकसान की भरपाई के लिए 52.14 करोड़ रुपये का मुआवजा किया जारी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 22,617 लाभार्थी किसानों के लिए 52.14 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की, जिनकी रबी फसलें 2025 सीजन के दौरान ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

यह फसल क्षतिपूर्ति की आकलन ह्यक्षतिपूर्ति पोर्टलह्य के माध्यम से एकत्रित व्यापक फसल क्षति आंकड़ों के आधार पर की गई है, जिसे दिसंबर 2024 और मार्च 2025 के बीच चालू किया गया था। राज्य भर के किसानों ने पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज कराया था, जिसके बाद गहनता से आकलन और सत्यापन किया गया। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि गहन सत्यापन के बाद लगभग 57,485 एक-ड़ भूमि मुआवजे के लिए पात्र पाई गई। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन में राज्य के 15 जिलों अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और यमुनानगर को शामिल किया गया और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल खराबे वाले जिलों में रेवाड़ी को सबसे अधिक 19.92 करोड़ रुपये, महेंद्रगढ़ को 10.74 करोड़ रुपये, झज्जर को 8.33 करोड़ रुपये, गुरुग्राम को 4.07 करोड़ रुपये, चरखी दादरी को 3.67 करोड़ रुपये तथा भिवानी को 2.24 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। अन्य जिलों को उनके सत्यापित प्रभावित क्षेत्रों और पंजीकृत किसानों के आधार पर अलग-अलग राशि जारी की गई है। इस मुआवजे का उद्देश्य 2025 के रबी सीजन के दौरान खराब मौसम की स्थिति के कारण होने वाले नुकसान से उबरने में किसानों की सहायता करना है। मुआवजे की राशि की गणना सत्यापित प्रभावित क्षेत्र के आधार पर और आपदा राहत के सरकारी मानदंडों के अनुसार की गई। दावों के सत्यापन और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र धनराशि जारी करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वितायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम.पांडुरंग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रेय सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे।

रामदेवरा में नेत्र कुंभ का आयोजन बाबा रामदेव के आदर्शों का प्रतीक-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

एसबी संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता की स्थापना करने और समाज में गरीब एवं वंचित लोगों की पीड़ा दूर करने का काम किया। इस धरा पर नेत्र कुंभ का आयोजन बाबा रामदेव जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और मानव कल्याण के उनके आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

श्री शर्मा गुरूवार को जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा सेवा जीवन में फिर से उजाले भरने जैसा पुण्य कार्य है। यह जनकल्याण और मानव सेवा की मिसाल है, जो सभी वर्गों के लिए समर्पित है।

श्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति एवं त्योहारों में सेवा का भाव सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि लोकदेवता बाबा रामदेव जी के मेले के शुभ अवसर पर आंखों के इलाज के लिए महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 अगस्त से 2 सितम्बर तक चलने वाले इस शिविर में सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही, 11 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके निवास के नजदीक चिकित्सालय में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय हमारी नीतियों का प्रमुख ध्येय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए हैं। नेत्र स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां की रोशनी फैलती रहे। प्रदेश में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी तथा नेत्र चिकित्सकों और सहायकों को नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण और अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेत्रदान के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों के जीवन को उजियारा मिल रहा है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) के माध्यम से गरीब और वंचित परिवारों को 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को बचाने का एक मानवीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रतिदिन लगभग 10 हजार लोगों को 10 करोड़ रुपए की राशि का कैशलेस उपचार मिल रहा है। साथ ही, मा वाउचर योजना लागू कर प्रतिमाह 25 हजार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा भी दी जा रही है। अब तक लगभग 2 लाख 87 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत वाउचर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पेपरलीक जैसी घटनाओं से युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। हमारी सरकार ने डेढ़ साल में ही पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल से अधिक कार्य किए है। उन्होंने कहा कि हमनें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब तक लगभग 24 हजार पदों पर भर्तियां की हैं और 26 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रिया में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती शूरवीरों के साथ लोक देवी-देवताओं और संतों की भूमि है। राज्य सरकार आस्था धामों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 18 हजार 328 यात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन, 55 ट्रेनों से 48 हजार 928 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर तथा लगभग 6 हजार श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के साथ हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।

भारत बनेगा प्रमुख आर्थिक शक्ति, व्यापार और उद्यमिता निभाएंगे अहम भूमिका: हरविन्द्र कल्याण

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और इस दिशा में व्यापार और उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी सरकार बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को लगातार बढ़ावा दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष बुधवार देर रात करनाल में एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह कार्यक्रम उन दूरदर्शी उद्यमियों और संस्थानों के सम्मान में आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि ऐसे फेलिसिटेशन कार्यक्रम केवल सम्मान देने के लिए नहीं होते, बल्कि ये उद्यमियों को नवाचार करने, नए व्यापार खड़े करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी और स्थायी विकास को भी सुनिश्चित करना है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो। उन्होंने कहा, उद्यमी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें सम्मान देना और उनके नवाचारों को पहचान देना एक सकारात्मक आर्थिक माहौल की नींव रखता है। हरियाणा सरकार इसी सोच के साथ राज्य को निवेश और उद्योगों के लिए आदर्श गंतव्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित उद्योगपतियों और व्यापारिक जगत के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार और उद्यमी मिलकर आगे बढ़ते हैं, तब देश की आर्थिक प्रगति में नई ऊंचाइयों को छूना संभव होता है।

समारोह में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। हरविन्द्र कल्याण ने अंत में कहा कि हरियाणा आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, और इसके पीछे राज्य के सशक्त, प्रेरित और नवोन्मेषी उद्यमी होंगे।

सरस्वती संयोसर जंगल में बनेगा 70 एकड़ में रिजर्व वायर, चिन्हित किए गए जंगल सफारी मार्ग

■ वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता की दिशा में बड़ा कदम

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। सरस्वती बोर्ड द्वारा वन विभाग के सहयोग से सरस्वती संयोसर जंगल में लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में रिजर्व वायर (संरक्षित क्षेत्र) विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से स्थल का दौरा किया गया, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और विभिन्न आवश्यकताओं पर चर्चा हुई।

हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती संयोसर जंगल में करीब 70 एकड़ में सरस्वती बोर्ड वन विभाग के साथ मिलकर रिजर्व वायर बनाएगा। जिसको लेकर सरस्वती संयोसर जंगल में विज़िट किया गया। यहां पर करीब 70 एकड़ जगह देखी गई और जंगल सफारी के लिए भी मार्गों को चिन्हित किया गया, ताकि आम लोग जंगल में रहने वाले पशु-पक्षियों और प्रवासी पक्षियों को नजदीक से देख सकें और उनके बारे में जान सकें। इसके तहत जंगल में एक सरोवर भी प्रस्तावित है, जिससे न केवल वन्य जीवों को पानी की सुविधा मिल सकेगी बल्कि वन क्षेत्र की हरियाली भी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडी बनाएँ, जिससे भू जल में भी सुधार हो और पशु पक्षियों को भी पानी मिल सके। अभी तक सरस्वती बोर्ड ने 15 के करीब वाटर बॉडी बनाई है। यह परियोजना न केवल जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम बनेगी। जंगल में उपयुक्त वातावरण मिलने से जीव-जंतुओं को सुरक्षित और अनुकूल निवास स्थान प्राप्त होगा, जिससे उनके अस्तित्व को संरक्षण मिलेगा।

इस विजिट के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने जंगल के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और प्रस्तावित कार्ययोजना पर सहमति जताई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास राजौंद में पानी की पाईप बिछाने का कोटा खत्म, काम अधूरा!

पाइपलाइन बिछाने का नया प्रारूप तैयार कर उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से आवंटन होने पर शेष बची पाइपलाइन बिछाई जाएगी: उपमंडल अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल द्वारा वार्ड 8 में पानी की पाइपलाइन न दबाने से खस्ताहाल गली। (छाया: एसबी)

संजना भारती संवाददाता

राजौंद। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल में पीने के पानी की पाइपलाइन का सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग द्वारा राजौंद के सभी वार्ड में सिवरेज पाइपलाइन व पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जानी है। लेकिन विभाग के पास पीने के पानी की पाइपलाइन कई महीने पहले खत्म हो चुकी है और काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

नागरिक जोगिंदर सिंह, काला राम, टोनी, अमन, नरेश कुमार, सेमी लाल, हीरा लाल सहित अन्य ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने वार्ड नंबर 11, सेवा क्लॉथ हाउस वाली गली, लाहोरिया वाली गली व वार्ड 8, नरेश पत्रकार वाली गली में सिवरेज पाइपलाइन दबाएं को कई महीने बीत गए हैं लेकिन विभाग ने पीने के पानी की पाईप लाईन अब तक नहीं बिछाई है। वार्ड 11 की दोनों गलियों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। वही वार्ड आठ में नरेश पत्रकार वाली गली में सिवरेज दबाई को कई महीने बीत गए हैं। गली कच्ची है। गली में नालियां नहीं बनाई गई है। घरों से निकलने वाले वेस्ट पानी से गली में कीचड़ व दल-दल जमा हो गया है स्कूल जाने वाले बच्चें, महीला, पुरुष, दिव्यांग, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल द्वारा पीने के पानी की पाईप लाईन दबाने के तुरंत बाद गली को पक्का करवा दिया जाएगा।

राजौंद की वंचित रही गलियों में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने के लिए दैनिक संजना भारती समाचार पत्र जिला ब्यूरो प्रमुख निर्मल कुमार ने मुख्यमंत्री हरियाणा से राजौंद की वंचित गलियों में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने का अनुरोध किया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपमंडल न. 4 के उपमंडल अभियन्ता द्वारा निर्मल कुमार को लिखे पत्र क्रमांक 3229 (28-07-25) में बताया है कि राजौंद की गलियों में जितनी पाइपलाइन बिछाने का एस्टीमेट भेजा गया था वह पाईप आ चुकी है और नगर में दबाई जा चुकी है। शेष रही गलियों में पाइपलाइन दबाने के लिए नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जो शीघ्र ही अनुमति हेतु उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। प्रारूप के स्वीकृति होने व कार्य आवंटित होने पर शेष बची पाइपलाइन को बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल अनुमान नहीं लग पाया कि राजौंद में कितनी पाइप लाइन बिछाई जानी है। अब बार बार अनुरोध करने पर भी विभाग पाइप मंगवा कर दबाने व पाइप खत्म होने की बात पिछले कई महीने से कर रहा है। राजौंद में चर्चा है कि विभाग द्वारा नगर के हिस्से की पाइपलाइन किसी और क्षेत्र में प्रयोग की गई है। विभाग के पास कितने काबिल आफिसर है, लेकिन वे यह अनुमान नहीं लगा पाए कि राजौंद में पीने के पानी की कितनी पाईप लाईन बिछाई जानी है। बार बार अनुरोध करने पर भी पाइप क्यों नहीं आ रही है।

इस पूरे मामले की जांच की मांग नागरिक कर रहे हैं। राजौंद की जो गलियां सिवरेज पाइपलाइन दबाने हेतु खोदी गई थी। जब तक पीने की पाइपलाइन नहीं दबाई जाती, तब तक नगर पालिका गलियों को पक्का बनाने में असमर्थता प्रकट कर चुकी है। राजौंद की टूटी-फूटी बदसूरत गलियों का जिम्मेदार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल है। लेकिन बदनामी नगरपालिका राजौंद को उठानी पड़ रही है।

नागरिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा से प्रार्थना की है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की जांच करवाएं ताकि राजौद में विभाग द्वारा कार्य में बर्ती गई अनियमित का पता चल सके। नागरिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा से नगर के वंचित वार्डों में पीने के पानी की पाइपलाइन शीघ्र दबवाने की मांग की है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए हो रही है कारगर साबित: डीसी

उपायुक्त कैथल प्रीति।

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है।

डीसी प्रीति ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है।

इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए।

राजौद में बंदरों का आतंक लगातार जारी

पुलिस थाना राजौंद में नगर पार्षदों, मौजिज नागरिकों व बंदर पकड़ने वाले ठेकेदार के बीच पंचायत बे-नतीजा खत्म

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौद में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अकेले जाते नागरिक को बंदर घेर कर काटने को दौड़ते हैं। सरकारी अस्पताल राजौंद में दवाई लेने पहुंचने वाले मरीजो, स्टाफ को बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। नगर के हर वार्ड में उत्पाती बंदरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नागरिक सोनू, सीमा, नवीन, कवीता, सुमन, आरती सहीत अन्य ने बताया कि बंदर बाहर सुख रहे कपड़ों को उठा ले जाते हैं। घरों में घुसकर रसोई, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, कीमती सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। टंकी के ढक्कन, पाइप, गाडी के वाइपर, प्लास्टीक गार्ड तोड़ देते हैं। कई नागरिकों को काटकर घायल कर चुके हैं।

पिछले दिनों राजौद के पार्षदों ने बंदर पकड़ने वाले ठेकेदार पर आरोप लगाए थे कि वह बंदरों को पड़कर आसपास ही छोड़ देता है जिस कारण से यहां पर बंदरों की संख्या कभी कम नहीं हो रही है। हालांकि ठेकेदार द्वारा लगाए गए आरोपो को बेबुनियाद बताया था। पार्षदों व ठेकेदार ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाना राजौद में शिकायत दी हुई है। गत दिवस पुलिस थाना राजौंद में नगर के पार्षदो, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व ठेकेदार पक्ष के बीच पंचायत हुई, जो बेनतीजा खत्म हो गई। पार्षद जॉनी राणा, अनुराग, बोगल सहित अन्य ने बताया कि जब तक ठेकेदार, पार्षदों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगता व राजौंद से पकड़े गए बंदरों को पार्षद प्रतिनिधियों के सामने जंगल में छोड़ने की बात स्वीकार नहीं करता। तब तक ठेकेदार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बताया गया कि ठेकेदार को एक बंदर पकड़ने के 1750 रुपए मिलते हैं। यह बहुत बड़ी रकम होती है। उसके बाद भी ठेकेदार अपना काम इमानदारी से नहीं कर रहा है। यह राजौंद के पार्षद स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि ठेकेदार उन पर गए लगाए गए आरोपो को बेबुनियाद करार दे रहे है। खबर लिखे जाने तक ठेकेदार व पार्षदों के बीच समझौता नहीं हो पाया था।

पीड़ित नागरिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा से अनुरोध किया हैं कि राजौंद नगर को उत्पाती बंदरों से मुक्ति दिलवाई जाए। नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा ने आशा प्रकट की है कि उन्हें उम्मीद है कि जनहित, नगरहित, सार्वजनिक हित में ठेकेदार व पार्षदों के बीच उत्पन विवाद का जल्दी हल निकलेंगा और नागरिकों को शीघ्र उत्पाती बंदरों से मुक्ति मिलेगी। नगर पालिका राजौंद हर समय नागरिकों की सहायता व सेवा के लिए तत्पर।

राजौंद में सिवरेज साईट पर ठेकेदार द्वारा नहीं लगाए साइन बोर्ड व बेरिकेट्स

सड़क पर धंस रहे भारी वाहन, जनता परेशान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद नगर में सिवरेज पाइपलाइन दबाने का कार्य नागरिकों, वाहन चालकों, राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ठेकेदार द्वारा कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी उदासीन दिखाई पड़ रहा है। सिवरेज साईट पर ठेकेदार द्वारा कहीं भी साइन बोर्ड व बेरिकेट नहीं लगाएं गए हैं। जिस कारण से बस, ट्रक, भारी वाहन कच्ची साईट पर धंस रहे हैं। सड़क पर दुकानों के सामने धंसे हुए वाहन घंटों खड़े रहते हैं। जिस कारण से दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है। जनता, राहगीर, वाहन चालक परेशान हो चुके हैं।

नागरिकों ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल व सिवरेज ठेकेदार बेपरवाह होते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है उन्हें जनता, वाहन चालकों, राहगीरों के दु:ख, परेशानी से कोई सरोकार नहीं रहा है। जनता की समस्या बारें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ जगदीश कुमार, जेई हरि सिंह, ठेकेदार सुनील कुमार को नगर के मेन रोड, सिवरेज पाइपलाइन दबाने की साईट, राजौंद के जींद चौंक के आसपास के क्षेत्र में बेरिकेडिंग करने व गड्ढे भरने का बार-बार निवेदन किया जा चुका है। इन अधिकारियों को मुख्य मार्ग पर धंसे हुए वाहनों की फोटो व वीडियो भी भेजी जा चुकी है। लेकिन इस जन समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा है।

नागरिकों विजय कुमार, सुखदेव, रवि, नवाब, सुनील कुमार, मामु राम सहित अन्य ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी से प्रार्थना करते हुए कहा है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल व सिवरेज ठेकेदार से सिवरेज साईट पर बेरिकेट लगवाएं, साइन बोर्ड लगवाएं। ताकि राहगीर, वाहन चालक, दुकानदार और अधिक परेशान ना हो।

नागरिकों ने निवेदन किया है कि राजौद के कैथल-असंध मार्ग पर जिस साइड में अपने सिवरेज दबाई है, विर्क होटल से जींद चौक तक सड़क एक साइड में काफी बैठ चुकी है। विभाग ने अनुरोध करने पर भी बैरिकेड नहीं लगाया है। रात के समय दो लोडिड ट्रक इसमें धंस गए थे। इस मार्ग पर यात्रियों से भरी बस व ट्रक पलटने से बच गए हैं। वाहन चालकों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। वाहन लगातार धंस रहें हैं। उसका जिम्मेवार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल व ठेकेदार हैं। नागरिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, सांसद कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल से इस जन समस्या का समाधान करवाने की अपील की है।

राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने गृह मंत्री से शिष्टाचार भेंट की

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद थी। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलकर मुझे बहुत शिक्षा मिली। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन और सुझाव दिए, जो हरियाणा के प्रशासन के संबंध में मेरे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे।

एचटेट लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न: डीसी

लेवल-1 में 2154 और लेवल-2 में 5956 अभ्यर्थी रहे उपस्थित

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाएं करनाल जिले में पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुईं। यह जानकारी उपायुक्त उत्तम सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को आयोजित इन दोनों परीक्षाओं के दौरान न केवल सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही, बल्कि परीक्षार्थियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि प्रात:कालीन सत्र में एचटेट लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में 6729 में से 5956 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 773 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, सायंकालीन सत्र में एचटेट लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा करवाई गई, जिसके लिए 9 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी। इस सत्र में 2562 अभ्यर्थियों में से 2154 ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 408 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पीने के पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थीं, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिससे यह साफ है कि परीक्षा सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। उन्होंने परीक्षा आयोजन में सहयोग करने वाले सभी विभागों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ किया।